करेंट अफेयर्स 7 सितंबर 2022

सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को लागू करने की याचिका पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी

SC ने महिला आरक्षण विधेयक, 2008 को फिर से पेश करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और याचिकाकर्ता को भारत संघ को नोटिस देने का निर्देश दिया।

संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।

इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों का एक तिहाई आरक्षित करना था।

हालांकि, यह 15वीं लोकसभा के विघटन के बाद 2014 में समाप्त हो गया।

महिला आरक्षण के पक्ष में तर्क

1. पंचायतों के अध्ययन ने महिलाओं के सशक्तिकरण और संसाधनों के आवंटन पर आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव दिखाया है।
2. विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों और पितृसत्तात्मक परंपराओं के कारण महिलाओं का राजनीति से ऐतिहासिक सामाजिक बहिष्कार।
3. निर्णय/नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

महिला आरक्षण के खिलाफ तर्क

1. यह महिलाओं की असमान स्थिति को कायम रखेगा क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं माना जाएगा।
2. महिला उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं की पसंद को प्रतिबंधित करता है।
3. चुनावी सुधार के बड़े मुद्दों जैसे राजनीति के अपराधीकरण और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र से ध्यान भटकाना।

पंचायत में प्रतिनिधित्व

- 'पंचायत', "स्थानीय सरकार" होने के नाते, एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 243डी का खंड (3) पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों की संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य है।
- महिलाओं के अधिकारों को कानूनी दर्जा प्रदान करने का विचार ऐतिहासिक पंचायती राज अधिनियम, 1992 (73वां और 74वां संविधान संशोधन) के साथ शुरू हुआ। यह ध्यान रखना काफी दिलचस्प है कि 'मन्नीना मागा (मिट्टी का पुत्र)', पूर्व प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 1996 में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का वास्तविक वादा किया था [...] ये है महिला विधेयक का अब तक का सफर[स्रोत],
- महिला आरक्षण विधेयक [संविधान (81वां संशोधन) विधेयक, 1996] पहली बार संसद में 12 सितंबर, 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार। विधेयक को संसद की बाधाओं से पार नहीं मिला। श्री गौड़ा की सरकार अल्पमत में आ गई और बाद में 11वीं लोकसभा भंग कर दी गई और इसलिए बिल व्यपगत हो गया।
- 1998 में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने महिला विधेयक [संविधान (84वां संशोधन) विधेयक, 1998] पेश करके एक और प्रयास किया। विडंबना यह है कि इस बार भी बिल लैप्स हो गया क्योंकि 12वीं लोकसभा को समय से पहले भंग करना पड़ा था। वाजपेयी की सरकार अल्पमत में!
- 23 दिसंबर, 1999 को निचले सदन में विधेयक पेश करने के साथ एक और प्रयास किया गया। लेकिन राजनीतिक सहमति के अभाव में इस विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

निवारक निरोध (पीडी) में पिछले साल की तुलना में असम में राजद्रोह के मामलों की संख्या 23.7% की वृद्धि,

भारत के संविधान में अनुच्छेद 22

22. कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण

(1) गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपने कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। पसंद

(2) गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और ऐसा कोई नहीं व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि के बाद हिरासत में रखा जाएगा

(3) खंड (1) और (2) में कुछ भी (ए) किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो फिलहाल एक दुश्मन विदेशी है; या (बी) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है

(4) निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा, जब तक कि (ए) एक सलाहकार बोर्ड जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों, जो न्यायाधीश हैं, या हैं, या नियुक्त किए जाने के लिए योग्य हैं। एक उच्च न्यायालय ने तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले रिपोर्ट की है कि उसकी राय में इस तरह के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है:

(5) जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी कानून के तहत बनाए गए आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, ऐसे व्यक्ति को उन आधारों के बारे में सूचित करेगा जिन पर आदेश दिया गया है और उसे आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करें

(6) खंड (5) में कुछ भी नहीं है कि प्राधिकरण को ऐसा कोई आदेश देने की आवश्यकता होगी जैसा कि उस खंड में संदर्भित किया गया है ताकि उन तथ्यों का खुलासा किया जा सके जिन्हें ऐसा प्राधिकरण सार्वजनिक हित के खिलाफ प्रकट करता है।

(7) संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है

a) जिन परिस्थितियों में, और मामलों के वर्ग या वर्गों में, प्रावधानों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है उपखंड (ए) के खंड (4);

b) अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ग या वर्गों के मामलों में निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है; तथा

c) उपखंड (ए) के खंड (4) के तहत एक जांच में एक सलाहकार बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया शोषण के खिलाफ अधिकार

IPC देशद्रोह को एक अपराध के रूप में परिभाषित करता है जब कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा या अन्यथा लाता है या घृणा या अवमानना में लाने का प्रयास करता है, या भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उत्तेजना या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है।

केदार नाथ बनाम बिहार राज्य, 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह सरकार या उसके उपायों के बारे में आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से जो कुछ भी पसंद करता है उसे कहने या लिखने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को हिंसा के लिए उकसाता नहीं है।

नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 7 सितंबर

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए 07 सितंबर को विश्व स्तर पर नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह सामूहिक जवाबदेही और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए वायु प्रदूषण की सीमा पार प्रकृति पर केंद्रित है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों (व्यक्तिगत, समुदाय, कॉर्पोरेट और सरकार) पर जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है।

नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022: थीम

इस वर्ष की थीम "द एयर वी शेयर" वायु प्रदूषण की सीमा पार प्रकृति पर केंद्रित है, जिसमें सामूहिक जवाबदेही और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शमन नीतियों और कार्यों के अधिक कुशल कार्यान्वयन के लिए तत्काल और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।

नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022: महत्व

संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के साथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाता है। उपस्थित लोगों ने अपने दृष्टिकोण रखे और दुनिया भर में वायु प्रदूषण और वायु गुणवत्ता के प्रभावों पर डेटा पर चर्चा की।

नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस: इतिहास

अपने 74 वें सत्र के दौरान, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर, 2019 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। इस संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को भी सहयोग में दिन के पालन की सुविधा के लिए प्रोत्साहित किया। अन्य प्रासंगिक हितधारक। प्रस्ताव के पारित होने की अगुवाई में, जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन ने यूएनईपी और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर दिन की वकालत की।

उत्तराखंड सरकार ने 'समर्थ' ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया

उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने एक ई-गवर्नेंस पोर्टल "समर्थ" लॉन्च किया। यह पोर्टल पांच राज्य विश्वविद्यालयों और 140 पब्लिक स्कूलों से प्रवेश परीक्षा, वेतन संरचना और नियुक्तियों के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट प्रदान करता है। राज्य में शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह पहल की गई है।

उत्तराखण्ड शासन

भारत बना दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

खबरों में क्यों?

हाल ही में भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है।

अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6-6.5% की वृद्धि नई सामान्य है और भारत 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।

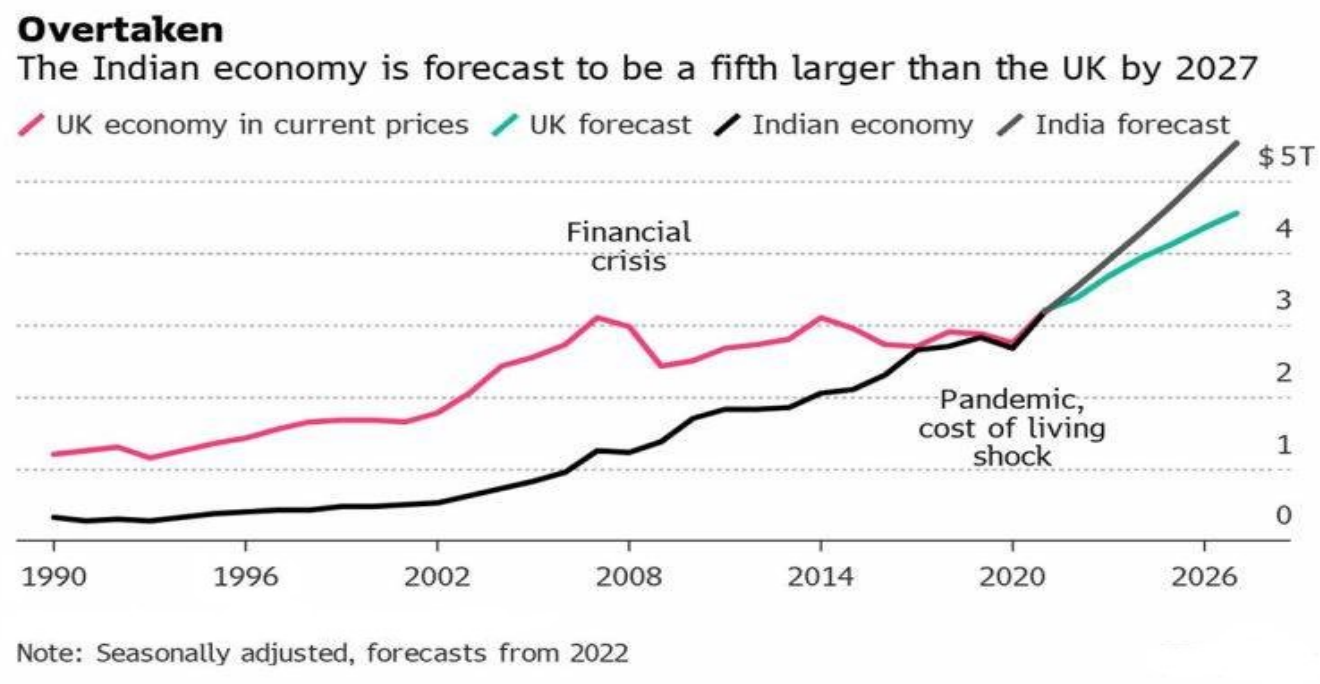

इस उपलब्धि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

नया मील का पत्थर:

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक को पीछे छोड़ना, विशेष रूप से दो शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाली अर्थव्यवस्था, एक प्रमुख मील का पत्थर है।

अर्थव्यवस्था का आकार:

मार्च, 2022 की तिमाही में 'नाममात्र' नकद शर्तों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 854.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि यूके के लिए 816 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

यूनाइटेड किंगडम के साथ तुलना:

जनगणना:

2022 तक, भारत की जनसंख्या 1.41 बिलियन है जबकि यूके की जनसंख्या 68.5 मिलियन है।

RACE IAS